खेल एवं युवा मामले :

178. वर्तमान में राज्य में 14 खेल अकादमियां (8 बालक एवं 6 बालिका) संचालित की जा रही हैं, जिनमें 252 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन अकादमियों के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक प्राप्त कर राज्य व राष्ट्र का नाम रोशन किया है। इन 14 अकादमियों के अतिरिक्त संभाग मुख्यालय कोटा में बालिका फुटबाल, भरतपुर में बालक कुश्ती तथा बीकानेर में साईक्लिंग अकादमी खोली जायेगी। इस पर 5 करोड़ 17 लाख रुपये का व्यय होगा।

179. झुंझुनूं में वॉलीबाल अकादमी की स्थापना की जायेगी। अकादमी के भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

180. खेलों के प्रति रूझान बनाये रखने हेतु प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के विशिष्ट श्रेणी के एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की जायेगी।

181. जनजाति समुदाय की लुप्त हो रही परंपरागत लोक संस्कृति एवं कला विधाओं के संरक्षण हेतु राज्यस्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस महोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर के पश्चात राज्य स्तर पर किया जायेगा।

182. जोधपुर, करौली एवं अलवर में निर्मित multi purpose indoor hall को उपयोग में लिये जाने हेतु indoor games के आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे, जिन पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

183. सवाईमानसिंह स्टेडियम जयपुर में निम्न सुविधाओं का विकास किया जायेगा:–

- हॉकी मैदान पर नया astroturf –लागत 4 करोड़ रुपये।
- Meditation Centre का निर्माण–लागत 35 लाख रुपये।
- निर्माणाधीन training track को सिंथेटिक किया जायेगा– लागत 2 करोड़ रुपये।

184. साथ ही, प्रदेश के निम्न स्टेडियमों में भी विकास कार्य करवाये जायेंगे:–

- विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर में सोलर लाईटों एवं विभिन्न निर्माण कार्य–लागत एक करोड़ 5 लाख रुपये।

- चौगान स्टेडियम, जयपुर में बास्केट बॉल कोर्ट, सिविल कार्य एवं indoor hall का निर्माण कार्य–लागत एक करोड़ 25 लाख रुपये।
- उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में interlocking basket ball court, synthetic basket ball court का निर्माण कार्य–लागत एक करोड़ 35 लाख रुपये।
- सूरतगढ़ स्टेडियम, श्रीगंगानगर में विकास कार्य–लागत 25 लाख रुपये।

185. राज्य सरकार खेलों में जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियमों में ढांचागत सुधार के लिए निजी जनसहभागिता योजना लायेगी।

186. निजी क्षेत्र में sports academy स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष में एक व्यापक नीति लायेगी।

187. युवा मामले एवं खेल विभाग के लिए आगामी वर्ष में 106 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान से 24.30 प्रतिशत अधिक है।